

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक: 3740 / मानचित्र-अनु0(जोन-ए) / 19

दिनांक : 31 : 12 : 2019

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

मै0 सरस्वती इन्फ्रा स्ट्रक्चर्स
द्वारा पार्टनर श्री वरुण अग्रवाल,
पुत्र श्री अमित कुमार,
नियामी -4, विजय नगर,
मेरठ।

विषय: तलपट मानचित्र सं0 MAP20191223130445090 की औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

आपके द्वारा मानचित्र संख्या- MAP20191223130445090 ग्राम नूरनगर, मेरठ के ख0सं0 293अ, 293ब क्षेत्रफल 17666.53 वर्ग मीटर भूमि भूमि पर भूखंडीय विकास/ निर्माण के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया था। जिस पर उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.12.2019 अनुक्रम में निम्न औपचारिकताएँ/ शर्तें पूर्ण की जानी आपेक्षित हैं:-

1- कुल देय वाहय विकास शुल्क अंकन रु0 1,64,93,472.41 प्राधिकरण कोष में जमा करने होंगे।

अथवा

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार वाहय विकास शुल्क अंकन 1,64,93,472.41 का 40 प्रतिशत अंकन रु0 65,97,388.94 एकमुश्त व अवशेष 60 प्रतिशत अंकन रु0 98,96,038.45 को 6 छमाही किश्तों में जमा करना होगा। जिस हेतु समतुल्य मूल्य की भूमि प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखनी होगी एवं समान धनराशि के 6 पोस्ट डेटिड चैक प्रस्तुत करने होंगे।

2- भावी ग्रामीण विकास शुल्क रु0 6,54,639.21 निरीक्षण शुल्क अंकन रुपये 2,64,997.95 लेबर सेस रु0 89,614.00, शैल्टर फीस रु0 21,31800/- व मानचित्र शुल्क रु0 15,000.00 प्राधिकरण कोष में जमा करने होंगे।

3- विकास कार्यों को प्रस्तावित सर्विसेज प्लान के अनुसार स्थल पर कराया जाना होगा।

4- आन्तरिक विकास कार्यों को मानकों के अनुरूप अपनी लागत पर पूर्ण करने होंगे और आन्तरिक विकास कार्य के प्रति निष्पादन गारंटी विक्रय योग्य भूमि के 20 प्रतिशत भाग को प्राधिकरण के पक्ष में रजिस्टर्ड मोरगेज/ बंधक कराने होंगे अथवा इतनी राशि की बैंक गारंटी मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में देनी होगी। जो आन्तरिक विकास कार्यों के पूर्ण होने के साथ-साथ समानुपातिक रूप से अवमुक्त की जायेगी। आन्तरिक विकास कार्यों को कराये जाने के संबंध में प्राधिकरण के साथ अनुबन्ध करना होगा।

5- आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6- आन्तरिक विकास कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात कालोनी नगर निगम अथवा आर.डब्लू.ए. को हस्तान्तरित करना होगा तथा कालोनी को नगर निगम/आर.डब्लू.ए. को हस्तान्तरित होने तक आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव की जिम्मेदारी कालोनाईजर की होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7- कालोनी के आन्तरिक विद्युतीकरण का समस्त कार्य उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 के मानकों के अनुसार अपने व्यय पर पूर्ण करना होगा तथा उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 का पूर्णतया प्रमाण-पत्र कालोनी के कम्प्लीशन पर प्रस्तुत करना होगा। इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8- कालोनाईजर द्वारा स्थल पर एस0टी0पी0/पीने के पानी की व्यवस्था/सीवर निस्तारण आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 9- कालोनी मे जंक्शन पर फायर हाईड्रेन्ड लगाने होंगे। इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 10- सर्विसेज प्लान के अनुसार स्थल पर विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं को यथा एन0बी0सी0/पी0डब्ल्यू0डी0 के मानको के अनुरूप विकसित करना होगा। इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 11- भू-स्वामित्व मिले-जुले खसरे के अकृषक/आवासीय प्रयोजन की है, जिसकी कुर्रबन्दी नहीं है, भविष्य मे किसी भी सहखातेदार से कुर्र बन्दी/रास्ता से सम्बन्धित कोई वाद/विवाद उत्पन्न होने की स्थित मे आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। इस आशय का शपथ -पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 12- नगर निगम मेरठ, अपर जिलाधिकारी मेरठ (प्रशासन), मेरठ एवं क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों मे अंकित शर्तों का पालन करना होगा। इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 13- कालोनी की आन्तरिक सड़को के दोनो ओर शासनादेशों के अनुसार वृक्षा रोपण करना होगा। इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 14- भूखण्डो पर निर्माण किये जाने से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने होंगे। इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 15- स्वीकृत मानचित्र का डिस्पले स्थल पर करना होगा। इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 16- कूड़ा निस्तारण/डस्टबिन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 17- स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा, जिस हेतु रू0 1,00,000/- की एफ0डी0आर0 प्राधिकरण के पक्ष में बंधक कर प्रस्तुत करना होगा।
- 18- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं0 21/2014वर्धमान कौशिक एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में पारित मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 10.11.16 का अक्षरशः पालन करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1. Owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including owner, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.
2. The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
3. All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.
4. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
5. The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
6. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
7. Owner shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.
8. It shall be the responsibility of owner to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
9. All owners/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.

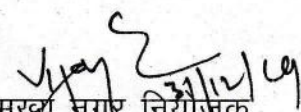


10. Wind breaking walls around constructin site.
11. All owners shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only.and due record in that behalf shall be maintained by the owners and transporters.
12. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
13. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
14. Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
15. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
16. Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.
17. Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.
18. Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.
19. Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.
20. Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.
21. Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).
22. Green belt creation will also act as a mitigating factor.

उक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.16 में उल्लेखित धनराशि पैनल्टी के रूप में वसूल की जायेगी।

अतः उपरोक्त समस्त औपचारिकतायें दिनांक 15.01.2020 तक पूर्ण कराकर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करे, जिससे कि आपके मानचित्र पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,


मुख्य सगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।